SHRI BHARATSINH SOLANKI: Sir, the supplementary put by the hon. Member does not arise out of the main question. The hon. Member should put a separate question for it.

MR. CHAIRMAN: This is not related to the main question. ...*(Interruptions)*...

*324. *[The questioner Shri Sabir Ali was absent. For answer *vide* page 23 *infra*]

*325. *[The questioner Shri Nandi Yellaiah was absent. For answer *vide* page 27 *infra*]

सैट-टाप बाक्स का प्रयोग करने वालों से बढ़ाई गई राशि का वसूल किया जाना

*326.**श्री रवि शंकर प्रसाद :††**
श्री शिवानन्द तिवारी :
क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सैट-टाप बाक्स पर सीमा शुल्क बढ़ाए जाने की घोषणा के बाद इस राशि को उपभोक्ता से वसूल किए जाने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर बढ़ाई गई सीमा शुल्क की राशि का एक समान वितरण किए जाने के संबंध मे निर्णय लेने के लिए हस्तक्षेप करेगी?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख गया है।

विवरण

(क) से (ग) ऐसा कोई निर्णय सरकार द्वारा अथवा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा नही लिया गया है। सीमा-शुल्क में वृद्धि के कारण सेट-टॉप बॉक्स (एसटीपी) की कीमत में होने वाली किसी भी वृद्धि को उपभोक्ता तक पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से अंतरित किए जाने और इस वृद्धि में से प्रसारण सेवा प्रदाता द्वारा वहन किए जाने वाले भाग के संबंध में कोई भी निर्णय प्रसारण सेवा प्रदाता के स्तर पर लिया जाता है।

Recovery of increased amount from set-top box users

†*326. SHRI RAVI SHANKAR PRASAD:†††
SHRI SHIVANAND TIWARI:
Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is fact that following announcement of hike in customs duty on set top box, a decision has been taken to recover this amount from consumers;

(b) if so, the details in this regard; and

(c) whether, in view of the protection of consumers, interests, Government would intervene for uniform distribution of the hiked customs duty?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI AMBIKA SONI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

†Original notice of the question was received in Hindi.
††सभा में यह प्रश्न श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा पूछा गया।
†††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ravi Shankar Prasad.

Statement

(a) to (c) No such decision has been taken either by the Government or by the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI). Any decision as to whether any increase in the price of STB due to an increase in Customs Duty is to be passed on to the consumer either in full or in part and the extent to which it is to be absorbed by the broadcasting service provider, is taken at the level of the broadcasting service provider.

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, मैंने माननीय मंत्री जी के उत्तर को देखा है, उनका उत्तर स्पष्ट नही है। माननीय मंत्री जी कृपया यह बताएं कि क्या सेट-टॉप बॉक्स पर 5 प्रतिशत ड्यूटी लगाई गई या नहीं लगाई है? क्योंकि आपका उत्तर है, 'No decision has been taken by the Government or by the Telecom Regulatory Authority of India' जहां तक हमें जानकारी है कि सेट-टॉप बॉक्स पर 5 प्रतिशत ड्यूटी लगाई गई है। मुझे यह भी पता है कि आपके विभाग ने यह अनुशंसा की थी कि यह ड्यूटी नहीं लगाई जानी चाहिए, क्योंकि देश में digitisation का काफी विस्तार हो रहा है, इसलिए यह लगाई गई है। जो ऑपरेटर्स हैं, वे यह कह रहे है कि इसके कारण डेढ़ सौ से दो सौ रुपए सेट-टॉप बॉक्स की कीमत बढ़ेगी, तो हम वह कीमत उपभोक्ताओं से वसूलेंगे। इससे तो उपभोक्ता परेशान होंगे। मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि उनको रेग्युलेशन में पावर है क्या सरकार TRAI के साथ बातचीत करेगी, ताकि इस संबंध में उपभोक्ताओं की परेशानी न बढ़े, सरकार इसके बारे में क्या कोई रास्ता सोच रही है?

श्रीमती अम्बिका सोनी : महोदय, मैं माननीय सांसद रवि शंकर प्रसाद जी को यह बताना चाहती हूं कि वे मुझसे पहले इस मंत्रालय में मंत्री रहे हैं और वे स्वयं यह जानते हैं कि TRAI इस मामले में दखल नहीं देती है और जो 90 से 125 रुपए पर सेट-टॉप बॉक्स पांच परसेंट कस्टम ड्यूटी के कारण कीमत बढ़ी है, इससे broadcasters को स्वयं तय करना है कि उसको किस तरह अपने में एब्जॉर्ब करेंगे या उपभोक्ताओं पर लागू करेंगे।

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय सभापति महोदय, मैं इसी सवाल को दूसरी तरह से प्रस्तुत करना चाहूंगा, आप मुझे इसकी अनुमति दें। TRAI का यह भी दायित्व है कि वह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करे, आप उनके रेग्युलेशन को कृपा करके विनम्रता से पढ़ें। यदि उपभोक्ता परेशान होता है, तो सरकार TRAI के सामने जा सकती है, broadcasters को बुलाकर इसका निदान कर सकती है। मैंने यह पूछा था कि क्या आपकी सरकार इस दिशा में कोई पहल कर रही है?

श्रीमती अम्बिका सोनी : सर, अभी कुछ दिन पहले ही पांच परसेंट ड्यूटी लगाई गई है। कुछ MSOs और broadcasters ने यह बयान दिया है कि शायद वह सौ रुपया पर सेट-टॉप बॉक्स बढ़ाएंगे। उन्होंने अभी तक कोई अंतिम फैसला नही किया है, लेकिन अगर उपभोक्ता परेशान होंगे, तो आवश्यक तौर पर मंत्रालय उनका हित TRAI तक जरूर ले जाएगा या जो भी फोरम होगा, तो आवश्यक तौर पर मंत्रालय उनका हित TRAI तक जरूर ले जाएगा या जो भी फोरम होगा, हम उस पर जाएंगे। मैं माननीय सांसद महोदय को यह बताना चाहती हूं कि हमने यह जरूर मांगा था कि Countervailing Duty है, उसको कम कर दिया जाए, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। इस मुल्क में जिस तरह से digitisation बढ़ता जा रहा है, मेरे पास सभी आंकड़े मौजूद हैं, यदि मैं वे आंकड़े यहां पर प्रस्तुत करूं, तो सदन यह जानकर बहुत खुश होगा कि हम digitisation की ओर बढ़ रहे हैं। जो हमारे यहां indigenous producers हैं, उन्होंने भी अपना एक संगठन बनाया है। मेरी उनसे दो बार बातचीत हुई है। आज वे इस स्थिति में हैं

कि वे अपनी indigenous प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। उनमें से एक तो एक्सपोर्ट भी कर रहा था। इनके अलावा कई और भी हैं, जो इस दिशा में यह समझते हैं कि पांच परसेंट कस्टम ड्यूटी में जो 100 रुपए बढ़ेंगे, इससे उनको अपना उत्पादन बढ़ाने में और प्रोत्साहन मिलेगा। मैंने उनको न सिर्फ अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा है, मैंने उनसे एक टाइम फ्रेम रेस्पांस मांगा है कि दो साल के अंतर्गत डिमांड को मीट करें, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए भी कीमत कम करें, ताकि लोगों को इम्पोर्ट करने की आवश्यकता न पड़े और देश में बना सेट-टॉप बॉक्स कम कीमत पर उपलब्ध हो सके। इससे रोजगार भी ज्यादा उपलब्ध होंगे और उपभोक्ता भी संतुष्ट होंगे।

श्री शिवानन्द तिवारी : सभापति महोदय, मैं माननीया मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि जब तक वह स्थिति नहीं आती है कि हमारे यहां का इंडिजिनस बॉक्स देश की जरूरत को मीट नहीं कर पाता है, उससे पहले जो हम आयात कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, उसके बारे में माननीया मंत्री जी ने कहा कि अगर उपभोक्ताओं को परेशानी होगी तथा कीमत बढ़ेगी और बढ़ी हुई कीमत उपभोक्ताओं को चुकानी पड़ेगी तो उनकी परेशानी बढ़ेगी। तो इन्होंने कहा है कि अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है कि जो बढ़ा हुआ दाम है, उसकी कीमत कौन बियर करेगा? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कीमत बढ़ाई जाए या उपभोक्ताओं से ली जाए, इससे पहले इंटरवीन करके ट्राई के साथ बातचीत करके कि बढ़ी हुई कीमत उपभोक्ताओं को नहीं देनी पड़े, क्या ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी?

श्रीमती अम्बिका सोनी : मान्यवर, यह सवाल अभी उठता नहीं है, क्योंकि जो ब्रोडकॉस्टर्स हैं, जो डी.टी.एच. - एम.एस.ओ. हैं, जो सैट टॉप बॉक्स प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने भी अभी कोई अंतिम फैसला नहीं किया है। आप भी मार्केट फोर्सेज से परिचित हैं, कई डी.टी.एच. प्लेयर्स हैं जो स्वयं मार्केट को विन ओवर करने के लिए, कंज्यूमर्स को विन ओवर करने के लिए निर्धारित कीमत से भी कम चार्ज कर रहे हैं। तो अगर हमने कुछ ऐसा pre-empt कर दिया तो जो आज कम दाम में मिल रहा है, शायद वह भी रुक जाए। तो मैं इसको व्यक्तिगत तौर पर, मंत्रालय के तौर पर, जैसा मैंने कहा कि मैंने दोनों तरफ के लोगों से बात की है, टाइम फ्रेम रेस्पांस मांगे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से वोल्यूम बढ़ता जा रहा है, 100 फीसदी वोल्यूम बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में सेट टॉप बॉक्स जो डिजिटाइजेशन के लिए अनिवार्य हैं, सरकार की तरफ से भी बहुत ऐसे कदम उठाए जाएंगे इस दिशा में और उपभोक्ताओं को यह कम कीमत पर मिलेगा।

*327. *[The questioners Dr. E.M. Sudarsana Natchiappan and Shri Santosh Bagrodia were absent. For answer *vide* page 28 *infra*]

*328. *[The questioners Shri V. Hanumantha Rao and Dr.T. Subbarami Reddy were absent. For answer *vide* page 29 *infra*].

Targets for power generation

*329.DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government is aware that there is shortage of machinery, equipments, forging materials, contractors and manpower, which is making it difficult for Government to achieve the targets of power generation;

(b) if so, how Government is going to solve this problem so that the target of addition of 78,000 MW is achieved in time;